



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1984/चैत्र 27, 1906

No. 119]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1984/CHAITRA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

सां०क०नि० 289(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं० प्रा० 119”

संविधान (राजस्व वितरण) सं० 2 आदेश, 1984

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 और 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
के प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्
निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं० 2
आदेश, 1984 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश
के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह कि केन्द्रीय
अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 270 के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए प्राय
पर करों के उतरे शुद्ध आयों का, जितने संघ की उपलब्धियों के संबंध
में संघ करों के शुद्ध प्रागम नहीं है, 2.19 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 1984

से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त
हुए प्रागम माने जाएंगे।

(2) 1 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उक्त
खण्ड के अधीन राज्यों को सौंपा जाने वाला प्राय पर करों के शुद्ध
प्रागमों का प्रतिशत, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक वे प्रागम संघ राज्य
क्षेत्रों से या संघ की उपलब्धियों के संबंध में संघ करों से प्राप्त हुए
आगम माने जा सकते हैं, पच्चास प्रतिशत होंगे और इस प्रकार सौंपी जाने
वाली कुल रकम राज्यों में निम्नलिखित रूप में वितरित की जाएगी:

राज्य	प्रतिशत
1	2
आन्ध्र प्रदेश	8.023
असम	2.522
बिहार	9.540
गुजरात	5.959
हरियाणा	1.819
हिमाचल प्रदेश	0.595
जम्मू-कश्मीर	0.818
कर्नाटक	5.442
केरल	3.950
मध्य प्रदेश	7.356
महाराष्ट्र	10.953

1	2
मणिपुर	0.188
मेघालय	0.178
नागालैण्ड	0.085
उड़ीसा	3.739
पंजाब	2.714
राजस्थान	4.364
तमिलनाडु	8.050
त्रिपुरा	0.258
उत्तर प्रदेश	15.429
पश्चिमी बंगाल	8.018

4. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट राशियां 1 अप्रैल, 1984 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संविधान निधि पर भारित होंगी।

राज्य	करोड़ रुपए में
असम	38.17
हिमाचल प्रदेश	91.15
जम्मू-कश्मीर	114.85
मणिपुर	56.08
मेघालय	40.27
नागालैण्ड	81.12
सिक्किम	11.96
त्रिपुरा	53.34
पश्चिमी बंगाल	7.89

(2) उप-पैरा (1) के अधीन राज्यों को संवेद्य कोई राशि या राशियां उस राशि या राशियों के अनिवार्य होंगी या होंगी जो अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संवेद्य हों।

5. संविधान (राजस्व वितरण) अधिनियम, 1979, 1 अप्रैल, 1984 से निरविश्रित हो जाएगा।

जैस सिंह

राष्ट्रपति'

[फा० 19(3) 84-एल-1]

र० वेंकट सूर्य पेरियास्वामी, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1984

G.S.R. 289(F).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 119

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 2 ORDER, 1984

In exercise of the powers conferred by articles 270 and 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1984.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) For the purposes of clause (2) of article 270, 2.19 per cent., of so much of net proceeds of taxes on income as does not represent the net proceeds of taxes payable in respect of Union emoluments shall represent the proceeds attributable to Union territories for the financial year commencing on the 1st day of April, 1984.

(2) The percentage of the net proceeds of the taxes on income, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories or to taxes payable in respect of Union emoluments, which is to be assigned to the States under the said clause in the financial year commencing on the 1st day of April, 1984 shall be eightyfive per cent; and the total amount to be so assigned shall be distributed among the States as follows :—

State	Percentage
Andhra Pradesh	8.023
Assam	2.522
Bihar	9.540
Gujarat	5.959
Haryana	1.819
Himachal Pradesh	0.595
Jammu and Kashmir	0.818
Karnataka	5.41
Kerala	3.950
Madhya Pradesh	7.356
Maharashtra	10.953
Manipur	0.188
Meghalaya	0.178
Nagaland	0.085
Orissa	3.739
Punjab	2.714
Rajasthan	4.364
Tamil Nadu	8.050
Tripura	0.258
Uttar Pradesh	15.429
West Bengal	8.018

4.(1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1984 as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it for that year :—

State	Rupees in crores
Assam	38.17
Himachal Pradesh	91.15
Jammu and Kashmir	114.85
Manipur	56.08
Meghalaya	40.27
Nagaland	81.12
Sikkim	11.96
Tripura	53.34
West Bengal	7.89

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979, shall, as from the 1st day of April, 1984, stand repealed.

ZAIL SINGH,

President."

[F. 19(3)/84-L.F.]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy